भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 398
गुरूवार, 25 जुलाई, 2024/3 श्रावण, 1946 (शक)

रोजगार सृजन

398. श्री नीरज शेखर:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) वर्ष 2023 में और 2024 के दौरान आज की तिथि तक हुए रोजगार सृजन का राज्य-वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) वर्ष 2023 में और 2024 के दौरान आज की तिथि तक ग्रामीण क्षेत्रों में हुए रोजगार सृजन का राज्य- वार और क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए इन इलाकों में कुछ नए क्षेत्रों की पहचान की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) से (घ): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है। नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्ट के अनुसार, 2022-23 के दौरान 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लिए सामान्य स्थिति पर अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) 56% था और ग्रामीण क्षेत्रों में, डब्ल्यूपीआर 59.4% था।

देश और ग्रामीण क्षेत्रों में 2022-23 के दौरान व्यापक उद्योग प्रभाग द्वारा सामान्य स्थिति पर श्रमिकों का प्रतिशत वितरण अनुबंध-I में है।

2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार अनुमानित कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) अनुबंध- II में दिया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा प्रकाशित केएलईएमएस (के: पूंजी, एल: श्रम, ई: ऊर्जा, एम: सामग्री और एस: सेवाएं) डेटाबेस अखिल भारतीय स्तर पर रोजगार के रुझान प्रदान करता है। डेटाबेस के नवीनतम आंकड़ों, 2023-24 के अनंतिम अनुमान के अनुसार, देश में रोजगार 2017-18 में 47.5 करोड़ की तुलना में वर्ष 2023-24 में बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया। 2017-18 से 2023-24 के दौरान रोजगार में कुल वृद्धि लगभग 16.83 करोड़ है।

रोजगार सृजन के साथ रोजगार क्षमता में सुधार सरकार की प्राथमिकता है। तदनुसार, भारत सरकार ने ग्रामीण क्षेत्रों सहित देश में रोजगार पैदा करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय/विभाग जैसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, इलेक्ट्रोनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय आदि विभिन्न रोजगार सृजन योजनाएं/कार्यक्रम कार्यान्वित कर रहे हैं जैसे प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), ग्रामीण स्व-रोजगार और प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई), दीन दयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम), प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई), उत्पादन-आधारित प्रोत्साहन योजना आदि। भारत सरकार द्वारा कार्यान्वित की जा रही विभिन्न रोजगार सृजन योजनाओं/कार्यक्रमों के विवरण को https://dge.gov.in/dge/schemes_programmes पर देखा जा सकता है।

*****

अनुबंध-I

राज्य सभा के दिनांक 24.07.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 398 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर व्यापक उद्योग प्रभाग द्वारा कामगारों का अनुमानित वितरण (% में)।

क्र.सं.	व्यापक उद्योग प्रभाग के अनुसार एनआईसी- 2008	2022-23	
		ग्रामीण	ग्रामीण+शहरी
1	कृषि	58.4	45.8
2	खनन एवं उत्खनन	0.3	0.3
3	उत्पादन	8.2	11.4
4	बिजली, पानी, आदि.	0.4	0.5
5	निर्माण	13.9	13.0
6	व्यापार, होटल एवं रेस्तरां	8.3	12.1
7	परिवहन, भंडारण एवं संचार	3.5	5.4
8	अन्य सेवाएं	7.0	11.4
	योग	**100.0**	**100.0**

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

अनुबंध- II

राज्य सभा के दिनांक 24.07.2024 के अतारांकित प्रश्न संख्या 398 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

वर्ष 2022-23 के लिए 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए सामान्य स्थिति के आधार पर देश में कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण (% में)

क्र.स.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	ग्रामीण व्यक्तियों	अखिल भारतीय
1	आंध्र प्रदेश	62.8	58.6
2	अरुणाचल प्रदेश	67.9	64.9
3	असम	54.7	54.5
4	बिहार	47.8	47.0
5	छत्तीसगढ	74.7	70.1
6	दिल्ली	35.7	45.8
7	गोवा	42.4	45.1
8	गुजरात	68.9	61.5
9	हरियाणा	44.7	44.9
10	हिमाचल प्रदेश	76.5	73.8
11	झारखंड	65.6	60.9
12	कर्नाटक	59.0	55.6
13	केरल	53.4	50.5
14	मध्य प्रदेश	69.0	63.4
15	महाराष्ट्र	63.2	57.6
16	मणिपुर	49.1	48.7
17	मेघालय	69.9	65.8
18	मिजोरम	58.2	55.2
19	नागालैंड	74.7	69.4
20	ओडिशा	60.7	58.9
21	पंजाब	50.8	50.2
22	राजस्थान	63.6	58.8
23	सिक्किम	77.9	74.0
24	तमिलनाडु	59.6	54.7
25	तेलंगाना	64.1	57.7
26	त्रिपुरा	55.6	54.3
27	उत्तराखंड	57.1	53.5
28	उत्तर प्रदेश	57.0	53.9
29	पश्चिम बंगाल	58.6	56.1
30	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	64.0	60.0
31	चंडीगढ़	57.1	45.6
32	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	70.1	65.0
34	जम्मू एवं कश्मीर	64.2	60.7
35	लद्दाख	57.5	57.0
36	लक्षद्वीप	40.3	35.5
37	पुडुचेरी	60.1	49.6
अखिल भारत		**59.4**	**56.0**

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई